मोदी के आशीर्वाद से.....

पेज एक का शेष

खरीद रहे हैं। इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए अदाणी समूह करीब 493 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके लिए कंपनी ने मंगलदास अमरचंद को नियुक्त कर दिया है।

आखिर अडानी को इस तरह से मीडिया पर कब्जा करने की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल अडानी को अपने विरुद्ध आने वाली खबरों को दबाना है और 2024 के चुनाव में माहौल मोदी के पक्ष में बनाना है। अब इंटरनेशनल एजेंसी Fitch ने भी अडानी समूह की तरक्की पर सवाल खड़े किए हैं।

Fitch रेटिंग्स की क्रेडिटसाइट्स ने कल अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अडानी समूह के आक्रामक विस्तार के अलावा कर्ज और कैश फ्लो को लेकर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में अडानी समूह के नए और असंबंधित व्यवसायों में प्रवेश करने पर भी चिंता जाहिर की गई है। क्रेडिटसाइट्स के विश्लेषकों का मानना है कि अडानी समूह के बैंकों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन के साथ मजबूत संबंध हैं और इस वजह से समूह को फायदा हो रहा है।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांसीसी मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर (आरएसएफ) द्वारा "प्रेस स्वतंत्रता के शिकारियों" होने के आरोप में 37 राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों की सूची में टॉप पर नामित किया गया था..... यह सारा खेल उन्हीं के निर्देशन में चल रहा है।

2009 में अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एनडीटीवी को 350 करोड़ रुपए दिये; इंडियाबुल्स, आईसीआईसीआई बैंक से लिया हुआ पुराना कर्ज चुकाने के लिए

(ब्याज की दर-0 प्रतिशत)

अंबानी एनडीटीवी को 13 साल से औसतन 35 - 40 करोड़ रुपए सालाना का 'अनुदान' दे रहा था, जिससे एनडीटीवी बिकने या दिवालिया होने से बचा हुआ था। एनडीटीवी को बचाने में अंबानी की कोई तो 'दिलचस्पी' रही होगी।

कुछ महीने पहले अंबानी का गठजोड़ एक और मीडिया कंपनी नेटवर्क18 से हो गया। अब एनडीटीवी में अंबानी की 'दिलचस्पी' अपना मूलधन निकालने की रह गई। इसके लिए वह इस 'दिलचस्पी' को बेचने के लिए बाजार में था और यह बात बाजार में आम होने की वजह से एनडीटीवी का शेयर दाम बढता ही चला जा रहा था। एनडीटीवी के प्रोमोटरों को अगर यह खबर नहीं थी तो इस चैनल को खबरें मिलती कहां से हैं? वैसे इसके प्रोमोटरों में एक सोनिया सिंह भी हैं। उनके पति का नाम और पिछले दिनों वे किस पार्टी से किस पार्टी में गए, ये जानकारी न हो तो कर लें।

खैर, अडानी मीडिया कंपनी खरीदने के इरादे का ऐलान कई महीने पहले ही कर चुका था। आखिर अंबानी ने एनडीटीवी में अपनी 'दिलचस्पी' अडानी को बेच दी। रिलायंस की ओर से परिमल नाथवानी द्वारा बाकायदा अडानी को इसके लिए बधाई दी गई है।

एनडीटीवी पिछले तीन दशक से भारतीय सत्ता तंत्र के बढते फासिस्ट रूझान के सफर में अत्यंत उपयोगी सेफ्टी वाल्व का काम करता रहा है, बहुतों के दिमाग में अभी भी जनतंत्र का भ्रम बनाए हुए है। यह इसकी सबसे बड़ी कामयाबी और शक्ति है। चुनांचे उसकी एक कीमत है। यही कीमत उसमें अंबानी और अडानी जैसों की 'दिलचस्पी' की वजह है। इस कीमत को बनाए-बचाए रखने के लिए एक लडाई होती दिखाई देना भी जरूरी है, दिखेगी भी।

-मुकेश असीम

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल कर्मियों के आपसी झगड़े से हड़कंप

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 23 अगस्त की शाम पांच बजे ड्यूटी खत्म करके सफाईकर्मी गोपाल व उसका सुपरवाइजर रविन्द्र अस्पताल से बाहर एक साथ निकले थे। दोनों चचेरे-मौसेरे भाई बताये जाते हैं। बाहर आंगन नामक रेस्तरां के सामने दोनों ने सिगरेट पी। उसके बाद दोनों में किसी बात को लकर मार-पीटाई हो गई, थप्पड़-घूंसे चले। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि किसी महिला सुपरवाइजर को लेके दोनों में तकरार हुई थी।

थप्पड़-घूंसे खाकर गोपाल भाग कर अस्पताल में आ गया। सीसी टीवी फुटेज के मुताबिक जब उसने अस्पताल परिसर में प्रवेश किया तो उसके जिस्म पर कहीं कोई खून के निशान नहीं थे। गोपाल कैमरों की नज़र बचा कर एक ऐसी जगह चला गया जहां शीशे के टूटे गिलास इत्यादि पड़े थे। समझा जाता है कि वहां उसने किसी नोकीले शीशे से अपने चेहरे पर कट लगाया। इससे निकला खून उसके चेहरे पर फैल गया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचे गोपाल को मरहम पट्टी करके दाखिल कर लिया गया।

गोपाल के अनुसार रविन्द्र ने पहले से बुला कर रखे गये बाऊंसरो से उस पर

रविन्द्र

गोपाल

कातिलाना हमला कराया था। इसे लेकर अस्पताल के तमाम कर्मचारियों में सुपरवाइजर रविन्द्र के प्रति भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने यकायक काम बंद कर दिया। उधर अस्पताल प्रशासन ने तुरन्त एनएच तीन पुलिस चौकी को सूचित कर दिया जिस पर पुलिस ने रविन्द्र के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके अलावा प्रशासन ने रविन्द्र सुपरवाइजर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।

अस्पताल प्रशासन की ओर से सामयिक एवं तत्परता से की गई कार्रवाई से हड़ताल पर उतारू तमाम कर्मियों को भी सारा मामला समझ में आ गया।

इसके साथ-साथ प्रशासन ने हड़ताल से मरीजों को होने वाले कष्ट से भी कर्मियों को आगाह कराया। सारे मामले को समझते हुए कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया।

अम्मा ने बनाया अस्पताल.....

पेज एक का शेष

पर दिये गये आईसीयू तथा डॉयलेसिस विभागों में खूब भुगता जा चुका है। ईएसआई वालों ने तो उन ठेकेदारों से मुक्ति पा ली है लेकिन बीके अस्पताल में हृदय रोग, डॉयलेसिस तथा एमआरआई आदि अभी भी ठेके पर लूट मचा रहे हैं। गौरतलब है कि अम्मा ने अपना कोई भी विभाग किसी ठेकेदार को नहीं सौंपा है। मोदी को यहीं से सबक सीख लेना चाहिये।

अस्पताल के बारे में बताया जा रहा है कि आरम्भ में 300-500 बेड ही खोले जायेंगे, फ़िर धीरे-धीरे मरीज़ों की संख्या के अनुसार बेड बढ़ाते जायेंगे। अस्पताल के जानकार सूत्रों के अनुसार इसे पूरी क्षमता तक पहुंचने में कम से कम पांच साल लग सकते हैं। मरीजों से क्या वसूला जायेगा इसके बारे में अभी तक खुल कर तो कुछ नहीं बताया जा रहा है लेकिन समझा जा रहा है कि ओपीडी कार्ड के लिये 300 रुपये वसूले जायेंगे जबकि यहां पर अन्य व्यापारिक अस्पतालों द्वारा इससे कहीं ज्यादा वसूले जा रहे हैं। जाहिर है हर नई दुकान पुरानी के मुकाबले में अपने दाम सस्ते रखती ही है। इसी ट्रस्ट द्वारा केरल व अन्य स्थानों पर चलाये जा रहे अस्पतालों में केवल कहने भर की ही रियायत गरीबों को मिलती है। यहां भी रियायत पाने वालों की एक श्रेणी अम्मा के भक्तों के रूप में पहले से ही तैयार है।

अस्पताल को चलाने के लिये इसे राज्य व केन्द्र सरकार के पैनलों पर भी रखा जायेगा अर्थात यहां इलाज कराने वाले सरकारी कर्मचारियों का बिल भुगतान सरकार करेगी। इसके अलावा बीते पांच साल से ठप्प पड़ी आयुष्मान योजना को भी इसके साथ जोड़ कर जीवित करने का प्रयास किया जायेगा। विदित है कि फ़िलहाल निजी अस्पताल आयुष्मान के तहत मरीज़ों को लेने से बचते आ रहे हैं।

अम्मा के अस्पताल में शोधकार्य

बताया जा रहा है कि चौदह मंजिला इमारत में चार मंजिल केवल शोध कार्य के लिये रखी गई हैं। किसी भी बड़े अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में शोध कार्य को एक अनिवार्यता माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान में दिन प्रति दिन नई-नई खोजें इसी के चलते सामने आ रही हैं। लेकिन ये कार्य केवल वहीं सम्भव हो पाते हैं जहां पर सरकार अथवा प्रबन्धन इस काम को प्रोत्साहित करे।

फ़रीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर, मुख्यालय के न चाहते हुए भी शोध कार्य में लगे रहते हैं क्योंकि यह उनके पेशे का एक अभिन्न अंग है। यदि वे इसको त्याग दें तो वे अपनी पेशेवर क्षमता में पिछड़ जायेंगे। **'मज़दूर मोर्चा'** प्रोफ़ेसरों द्वारा तैयार किये गये ऐसे महत्वपूर्ण शोध पत्रों का उल्लेख कई बार कर चुका है।

जरा ईएसआई मेडिकल सेवाओं की ओर भी झांक लेते मोदी जी

संदर्भवश, जनता को स्वास्थ्य सेवायें देने में मोदी सरकार की रुचि को समझने के लिये ईएसआई कार्पोरेशन की कार्यशैली को देखा जा सकता है। गुड़गांव क्षेत्र में ईएसआई कवर्ड 20 लाख मज़दूर हैं यानी कि 20 लाख परिवार, जिनके वेतन का साढे चार प्रतिशत ईएसआई कार्पोरेशन वसूल लेती है। इसके बदले इस क्षेत्र में मात्र 100 बेड का एक व 50 बेड का दूसरा अस्पताल है। इनकी कार्य क्षमता किसी अच्छी डिस्पेंसरी से अधिक नहीं है।

मोदी राज के आठ साल पूरे होने पर मानेसर में 500 बेड के एक अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। इसके लिये मात्र साढे सात एकड़ ज़मीन 120 करोड़ में खरीदी गई। अम्मा की दूर-दृष्टि तथा पैसे का सदुपयोग देखिये कि उन्होंने साढे छः सौ करोड़ में 133 एकड़ जमीन खरीद कर आगामी 50 साल तक कि विस्तार योजना तैयार कर ली जबकि उनके पास तैयार मरीजों की कोई सूची नहीं है।

उधर कार्पोरेशन जिसके पास पहले से ही 20 लाख मज़दूर परिवारों यानी कुल संख्या जोड़ें तो 80 लाख सम्भावित उन लाभार्थियों की सूची मौजूद हैं जो बाकायदा कार्पोरेशन को अपने वेतन का साढे चार प्रतिशत देते आ रहे हैं। यह मोदी सरकार की सोच एवं दूर-दृष्टि का अभाव ही तो है जो उसने मात्र साढे सात एकड़ का प्लॉट और वह भी इतने महंगे दामों में खरीदा।

यदि मोदी सरकार वास्तव में ही मज़दूरों की भलाई एवं उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने की सोच व समझ रखती तो इन्हीं 120 करोड़ रुपयों से उस क्षेत्र में 150-200 एकड़ ज़मीन खरीद सकती थी। संभावित लाभर्थियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए वहां दो से तीन हजार बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाता। इतने बड़े अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज, व पैरामेडिकल कॉलेज इत्यादि खोले जा सकते थे। मजे की बात तो यह है कि इस पर खर्च करने के लिये ईएसआई कार्पोरेशन के पास मज़दूरों का डेढ़ लाख करोड़ रुपया जमा पड़ा है।